Volume-7, No. 2 Aug.-2020, pp. Hin.41-45

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की विदेश नीति

श्री राजेश भाटी शोधार्थी
राजनीति विज्ञान विभाग
डा. संजय मिश्रा, राजनीति विज्ञान विभाग
एम.एम.एच. कालिज गाजियाबाद उ.प्र. भारत।
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ उ.प्र. भारत।

राष्ट्र के जीवन में आंतरिक शांति, आर्थिक संपन्नता, सामाजिक समरसता, शैक्षणिक विकास और स्वस्थ नागरिक जीवन की जितनी आवश्यकता होती है उससे कहीं अधिक आवश्यकता विदेशी राज्यों से मधुर संबंध बनाए रखने की है। इसलिए प्रत्येक राष्ट्र को अपनी विदेश नीति को ऐसे आयाम देने की आवश्यकता पड़ती है जो सामरिक, भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टियों से दूसरे देशों से संबंधों को मजबूत बनाने में सहायक हो। प्राचीन राष्ट्र होने के नाते भारत की विदेश नीति विश्व की सबसे पुरानी विदेश नीति मानी जाती है। जिसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह कभी भी विस्तारवादी नहीं रही है। अपने सामाजिक, सांस्कृतिक तथा व्यापारिक संबंधों को भारत ने अपने शांति पूर्ण व्यवहार से ऐसा मधुर बनाया कि जहां भी भारतीय उद्यमी, बुद्धिजीवी और विद्वानगण गए, उस देश को भी भारतीय रूप में परिदर्शित कर दिया।

मुख्य शब्द– नरेन्द्र मोदी, विदेश नीति, पडोसी देश, एक्ट ईस्ट नीति, प्रवासी भारतीय।

पौरुष का उपयोग जब सामाजिक और राष्ट्रीय कार्यों में नहीं होता है तो वह विलासी और भ्रष्ट हो जाता है। दुर्भाग्य से यही स्थिति भारत के साथ हो गई। भारत सरकार अपने को इतना दुर्बल मानने लगी कि वह शक्ति रहते हुए भी कुछ करने में असमर्थ प्रतीत हो रही थी। भारत की पुरुषार्थी जनता ऐसी सरकार से उब गई थी और संयोगवश उसे नरेन्द्र मोदी के रूप में एक दूरदर्शी एवं कर्मठ नेतृत्व मिला जिसका उसने वरण किया। नरेन्द्र मोदी एक तरफ भारत की दुर्बलता को दूर करने में लगे हैं और दूसरी तरफ भारत को उसके रूप और आकार के अनुसार विश्व के मंच पर उचित स्थान दिलाने के लिए दिन–रात बिना रुके–थके अपने प्रयास में लगे हैं। नरेन्द्र मोदी सरकार की साधना के फलस्वरूप विगत पांच वर्षों में भारत अपनी दुर्बलता को परित्याग कर विश्व बिरादरी में हर जगह सम्मान पूर्वक दिखाई पड़ रहा है। एक तरफ पुराने मित्र घनिष्ठता के साथ जुट रहे हैं तो दूसरी तरफ नये मित्र तेजी से बनते जा रहे हैं।

किसी देश की विदेश नीति उसके राष्ट्रीय हितों के अनुरूप दूसरे देशों के साथ आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा सैनिक विषय पर पालन की जाने वाली नीतियों का समुच्चय होती है, न तो किसी देश की परिस्थिति एवं न ही दुनिया की परिस्थिति सदैव एक समान रहती है। इसलिए बदलती अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति में राष्ट्रीय हितों के दृष्टिकोण से समयानुसार किसी भी देश की विदेश नीति में परिवर्तन होना स्वाभाविक है। यही कारण है कि कोई देश न तो किसी का स्थायी मित्र होता है और न ही स्थायी शत्रु। इक्कीसवीं सदी के पहले दशक में इसे दुनिया में तेजी से उभरती हुई एक शक्ति के तौर पर देखा जाता है। भारत को भी अपने राष्ट्रीय हितों को देखते हुए समय–समय पर अपनी विदेश नीति में परिवर्तन करना पड़ा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति भारतीय अर्थव्यवस्था के बदलाव के लिहाज से अधिक सफल रही है। अपने कार्यकाल के पहले वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 देशों में 53 दिन बताए। विदेशी यात्राओं के लिए उनकी आलोचना भी हुई, लेकिन यह बात सत्य है कि जब तक आप किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष के पास नहीं जाएंगे तब तक आपके संबंध उससे अच्छे नहीं बन पाएंगे। मोदी द्वारा संसार में भारत के प्रभाव क्षेत्र के विस्तार को लेकर प्रसिद्ध भारतीय अकादमी पत्रकार और विदेश नीति के विश्लेषक डॉ राजा मोहन ने लिखा है कि "प्रधानमंत्री मोदी की दीर्घकालिक विदेश नीतियों के लक्ष्य तथा उनकी राजनीतिक इच्छाशक्ति ने 2014 के मध्य से मजबूती के साथ भारतीय कूटनीति में असामान्य ऊर्जा भर दी है।"[1] प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सभी प्रयासों ने तीसरे गणराज्य के उस उषाकाल के निर्माण का संकेत दिया है जो भारत को अपनी इस महत्वाकांक्षा को महसूस कराये कि वो नेतृत्वशाली है।

भारत की मौजूदा विदेश नीति को जानने के लिए कुछ घटनाओं पर दृष्टिपात करते हैं– मैडिसन स्कवॉयर गार्डन वाली घटना एवं वहां 30 से अधिक अमेरिकी सांसदों की उपस्थिति, राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मीटिंग, 26 जनवरी के अवसर पर बराक ओबामा का भारत दौरा, क्योंटो में शिंजो अबे के साथ प्रधानमंत्री की निकटता, संसार के ताकतवर देशों के राष्ट्राध्यक्षों का बारी–बारी से भारत का दौरा करना, भारतीय प्रधानमंत्री का मध्य एशिया, पूर्वी एशिया या हिन्द महासागर के एकीकृत दौरे करना। क्या ये सब अब तक चलती रही कूटनीति की तरह ही हैं?

पड़ोसी देश

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विदेश नीति के मामले में पूर्व की सरकारों की तुलना में अपने पड़ोसी देशों पर ज्यादा ध्यान दिया है। दक्षिण एशिया में भारत के प्रभाव क्षेत्र पर पकड़ बनाने तथा चीन की बढ़ती भूमिका पर लगाम लगाने को लेकर उन्होंने अपने शपथ ग्रहण समारोह में अपना रुख स्पष्ट कर दिया था, जब उन्होंने दक्षिण एशियाई देशों के राष्ट्राध्यक्षों को समारोह में आमंत्रित किया था। "प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का पहला दौरा भूटान का था। यूपीए–1 के दौरान डॉ मनमोहन सिंह का पहला विदेशी दौरा बंगाल की खाड़ी के आस–पास वाले देश बिम्सटेक का था। यूपीए–।। के दौरान डॉ सिंह ब्रिक्स तथा शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेने गए थे। प्रधानमंत्री मोदी बाद में सार्क शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए काठमांडू गए। उन्होंने मई 2015 में देश के भू–सामरिक हितों के लिए हिन्द महासागर के महत्व को स्पष्ट करने के लिए सेशेल्स, मॉरीशस तथा श्रीलंका की यात्राएं की। इन देशों में आधारभूत संरचनाओं की परिसंपत्तियों को मजबूती से विकसित करने के लिए कई योजनाएं बनाई गई। भारत ने मालदीव में पेयजल संकट को दूर करने तथा नेपाल में भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए कई तरह की जरूरी आपूर्ति हवाई मार्ग के जरिए शीघ्रता से करायी। पहले पड़ोसी वाला दृष्टिकोण निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है।"[2]

भारत और पाकिस्तान के बीच काफी लंबे समय से बना तनाव इस क्षेत्र की समग्रता पर परेशानियों के बादल मंडराने का मुख्य कारण रहा है। भारत ने पाकिस्तान के साथ शांति के लिए काफी प्रयास किए हैं, लेकिन पाकिस्तान हमेशा कश्मीर का राग अलापता रहा है। भारत ने कश्मीर मामले पर अपनी कूटनीति से पाकिस्तान को विश्व पटल पर अलग–थलग कर दिया है। इस प्रकार भारत, बांग्लादेश, नेपाल एवं भूटान जैसे अन्य देशों ने फैसला कर लिया है कि उन्हें पाकिस्तान के बिना ही क्षेत्रीय एकता को लेकर आगे बढ़ना है। 15 जून 2015 को बांग्लादेश, भूटान, भारत तथा नेपाल (बीबीआईएन) ने यात्रियों माल–ओ– असबाब तथा अधिकारियों की यात्रा को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।

भारत ने बांग्लादेश के साथ विपक्षीय तथा ढांचागत संधियों की पकड़ बनाए रखने के लिए एक करार किया है, जिसका लक्ष्य सड़क, रेल समुद्र, विद्युत निकासी लाइन्स, पैट्रोलियम पाइपलाइन तथा डिजिटल जुड़ाव है। इन आवश्यक आधारभूत संरचनाओं के आपस में जुड़ने से विकास पर बहुगुणित प्रभाव पड़ेगा। बहुप्रतीक्षित भू–सीमा संधि पर हस्ताक्षर की तुलना बर्लिन की दीवार गिराने से होती रही है।

पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए अफगानिस्तान में समुंद्र और भूमि के रास्ते अपनी पहुंच बनाने के लिए भारत ने ईरान के साथ चबहार बंदरगाह के विकास को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे भी मध्य–पूर्व एशिया तक भारत को अपनी पहुंच बनाने में सहायता मिलेगी। इस बंदरगाह का इस्तेमाल कच्चे तेल तथा यूरिया के लिए किया जा सकेगा तथा इसमें परिवहन लागूत में भी बचत होगी। भारत का इरादा कंटेनर टर्मिनल तथा एक बहुउद्देशीय कार्गो टर्मिनल के लिए चबहार में दो बर्थ को पटटे पर लेने का है।

"इसका परिणाम यह है कि दक्षिण एशिया में माल–ओ–असबाब. सेवा तथा जनोन्मुख प्रभाव में एक मुक्त प्रवाह आ गया है। इस क्षेत्र में एक बेहतर कनेक्टिविटी से निजी तथा सार्वजनिक स्रोतों से निधि का उपयोग आधारभूत संरचनाओं में विशाल निवेश के रूप में हो सकेगा। इस सबका आर्थिक लाभ कई स्तरों पर होगा, यदि इनके बीच राजनीति नहीं आती है तथा पाकिस्तान अपने पूरे मन के साथ क्षेत्रीय एकता की प्रक्रिया में अपनी भूमिका निभाता है। तो दक्षिण एशिया विश्व में सबसे तेजी के साथ विकास करने वाला क्षेत्र बनेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नीति कनेक्टिविटी तथा सहयोग वाली है, जो इस क्षेत्र की आर्थिक गतिशीलता को मजबूती ही देगी। प्रधानमंत्री मोदी अपने पूर्ववर्ती की तुलना में हिन्द महासागर की सामरिक नीति को आकार देने में बहुत आगे निकल गए हैं। मार्च 2015 में उनका सेशेल्स, मारीशस तथा श्रीलंका दौरा जबरदस्त रूप से देशहित के विचार से महत्वपूर्ण बन गया।"[3]

पूर्व तथा पश्चिम क्षेत्र

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लुक ईस्ट नीति के स्थान पर एक्ट ईस्ट नीति को अपनाया है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन आसियान भारत की एक्ट

ईस्ट नीति का अभिन्न हिस्सा है। भारत समुद्री सुरक्षा, नीली अर्थव्यवस्था व मानवीय सहायता के क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करने का इच्छुक है। आसियान के दस सदस्य देशों के साथ भौतिक व डिजिटल रूप से कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने एक अरब डालर के लाइन आफ क्रेडिट का प्रस्ताव दिया है। नवंबर 2019 में भारत–आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लेते हुए थाईलैंड में मोदी ने कहा कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी का अभिन्न हिस्सा है और हमेशा रहेगा। एकीकृत व प्रगतिशील आसियान भारत के हित में है। उन्होंने भारत और आसियान के बीच भारत प्रशांत दृष्टिकोण का भी स्वागत किया और कहा कि भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, भारत–प्रशांत दृष्टिकोण का मुख्य हिस्सा है। भारत की मंशा नवाचार, शोध, पर्यटन, व्यापार और दोनों तरफ के लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने की है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जापान, अमेरिका, चीन, दक्षिण कोरिया अन्य देशों की यात्रा इस विचार से की ताकि उच्च गति वाली रेल, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क तथा उच्च राजपथ के निर्माण में सहायता करने के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेशों को आसानी से आकर्षित किया जा सके। इससे स्पष्ट होता है कि किस तरह बाहरी स्रोतों के प्रयोग द्वारा आंतरिक लाभ उठाया जा सकता है। डॉ मनमोहन सिंह के पास हिमालयी क्षेत्र से प्रशांत क्षेत्र तक फैले एशियाई बाजार को जोड़ने वाला दृष्टिकोण अवश्य था लेकिन वो मंगोलिया तक की भी यात्रा नहीं कर पाए ताकि पूर्व की तरफ देखने का शुभ संकेत मिल पाता। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने मंगोलिया से संबंध बढ़ाने के लिए वहां की यात्रा की।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ब्रिक्स सर्किट के समूह पर काम किया है, जो वैश्विक रूप से जीडीपी के पांचवें हिस्से, जनसंख्या के 43 प्रतिशत, व्यापार के 17.3 प्रतिशत तथा कृषि उत्पादन के 45 प्रतिशत में अपना योगदान देता है। विश्लेषकों का ब्रिक्स के बारे में मानना है कि यह एक मझोले आकार की अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके पास विश्व की सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था वाले देश यूएस के मुकाबले नेतृत्व करने की क्षमता है। ब्रिक्स के देश आपस में एक दूसरे के साथ व्यापार के लिए दिलचस्पी दिखा रहे हैं। अंतर्ब्रिक्स व्यापार का लक्ष्य 2015 तक 500 डॉलर के कारोबार को हासिल करना है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री ने सदस्य देशों का आह्वान किया कि इस राह में आने वाली बाधाओं को दूर किया जाए जो इस समय देशों के बीच वजूद में है। इस पहल में ब्रिक्स के अंतर्गत सीमा शुल्क समझौतों पर हस्ताक्षर करना भी सम्मिलित है। ब्रिक्स के सदस्य व्यापार करने के लिए अपनी स्थानीय मुद्राओं के उपयोग की शुरुआत करने के लिए भी उत्सुक हैं। भारत ने ब्रिक्स व्यापार मेले की मेजबानी करने की इच्छा जतायी है। लेकिन इन देशों के बीच भौगोलिक दूरी इस समूह के भीतर वाणिज्य तथा व्यापार के मार्ग में संभवतः सबसे बड़ी बाधक है। फिर भी, विश्व अर्थव्यवस्था में इस समूह का प्रभाव तथा महत्व इतना अधिक है कि इसे उपेक्षित नजरों से नहीं देखा जा सकता है।

मोदी सरकार की अन्य विदेश नीति उपलब्धि में, प्रवासी भारतीयों को भारत के विकास में भागीदार बनाना रहा है। विदेशी दौरों पर किसी रॉक स्टार की तरह प्रधानमंत्री का स्वागत किया जाना इस बात का संकेत है कि प्रवासियों का देश के साथ एक रिश्ता बना लिया गया है। यूएस, यूके, कनाडा तथा ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित देशों में बसे अनिवासी भारतीयों का इन देशों की राजनीति पर बड़ा प्रभाव है। इसका प्रयोग भारत के साथ द्विपक्षीय समझौतों को समीप पहुंचाने में एक लॉबी की तरह किया जा सकता है।

"प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संयुक्त अरब अमीरात के दौरे के पीछे का मकसद भी इन्हीं प्रवासियों तक पहुंचना था। 1981 के बाद किसी भी प्रधानमंत्री का इस तरह का यह पहला दौरा था। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की प्राथमिकता में पश्चिमी एशिया नहीं था। एक निर्वाचन क्षेत्र की अनदेखी करने के लिए 2.6 लाख प्रवासियों की संख्या बेहद महत्वपूर्ण है। वहां से जो धन वो अपने घर भेजते हैं, क्या वह इतने महत्वपूर्ण है। इन देशों में पहले से ही निर्मित आधारभूत संरचना के अंधकार में भोज के बारे में क्या कहा जा सकता है? भारत की ऊर्जा स्वाधीनता के बारे में क्या? इसमें कोई शक नहीं कि प्रधानमंत्री की यात्रा इन क्षेत्रों को भारत की विदेश नीति का एक अभिन्न भाग बनाती है।"[4]

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि देश को विकास पथ पर ले जाना है तो महाशक्तियों के साथ–साथ पड़ोसी देशों के साथ मधुर संबंध बनाना होगा। इसी दूरगामी नीति के तहत उन्होंने 2014 में प्रधानमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह में दक्षिण एशियाई देशों के राष्ट्र अध्यक्षों को आमंत्रित किया था। प्रधानमंत्री ने अपनी विदेश यात्राओं की शुरुआत भी भूटान से की। उनकी इस पहल का सकारात्मक परिणाम निकला और पाकिस्तान को छोड़कर सभी दक्षिण एशियाई देशों के साथ भारत के संबंध सुधरे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने दुनियाभर में भारत के हितों को आगे बढ़ाने

के लिए विदेश यात्राओं की मुहिम शुरू की। चाहे अमेरिका का मैडिसन स्क्वायर हो या ब्रिटेन का वेम्बले स्टेडियम, हर जगह प्रधानमंत्री ने भारत का गौरव बढ़ाया। इस उपलब्धि पर जहां दुनिया भर में भारतीय इतरा रहे हैं, वहीं विरोधी दल के नेताओं ने मोदी की विदेश यात्राओं पर आरोपों की झड़ी लगा दी। कभी कहा गया कि मोदी जनता के पैसे से दुनिया की सैर कर रहे हैं और कभी कहा गया कि वह ढोल–नगाड़ा बजा रहे हैं। किसी ने उन्हें 'एन. आर.आई. प्रधानमंत्री' कहा तो किसी ने संसद में आने के लिए पासपोर्ट देने की मांग उठाई। लेकिन मोदी इन आलोचनाओं से बेफिक्र होकर संबंध सुधार की अपनी मुहिम में लगे रहे।

"सप्रंग सरकार में भ्रष्टाचार, नीतिगत पंगुता आदि के कारण भारत के प्रति विदेशी निवेशकों के मन में अविश्वास और असमंजस की स्थिति पैदा हो गई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी विदेश यात्राओं के जरिए निवेशकों–उद्ययोगपतियों को भारत में निवेश करने का निमंत्रण दिया। उन्होंने निवेशकों को किसी भी सूरत में पैसा नहीं डूबने की गारंटी देते हुए खुलकर निवेश करने को कहा। अपनी जापान यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने यहां तक कहा कि हमारे यहां अब रैड टेप नहीं निवेशकों के लिए रेड कार्पेट बिछा है। नरेन्द्र मोदी ने 'मेक इन इंडिया', 'डिजिटल इंडिया' जैसे अभियानों के जरिए भारत को एक ब्रांड के रूप में स्थापित किया, जिससे भारत की दुनिया भर में धाक जमी और निवेशकों का विश्वास लौटा। इन्हीं विदेश यात्राओं का परिणाम है कि विदेशी निवेश में तेजी से बढ़ोतरी हुई और 2015 में भारत दुनिया भर में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने वाला देश बना।"[5]

चीन लंबे समय से भारत को चारों ओर से घेरने की रणनीति के तहत पाकिस्तान के साथ–साथ श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव में अपनी उपस्थिति बढ़ाने में लगा था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आक्रमक विदेश नीति का परिचय देते हुए चीन को चारों ओर से घेरने के लिए दक्षिण–पूर्व एशियाई देशों के साथ संबंध सुधार को प्राथमिकता दी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया, जापान, दक्षिण कोरिया के साथ रिश्तों को एक नया आयाम दिया। चूंकि चीन की आक्रामकता से दक्षिण एशियाई देश चिंतित हैं, इसलिए उन्होंने भारत की संबंध सुधार पहल को हाथों हाथ लिया।

मोदी सरकार ने पूर्व सरकार की लुक–ईस्ट नीति को एक्ट–ईस्ट नीति में बदल दिया। दक्षिण–पूर्व एवं पूर्वी एशियाई देशों के साथ भारत की सांस्कृतिक एकता की सुदीर्घ परंपरा रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसी सांस्कृतिक रिश्तों को प्रगाढ़ बनाकर जो आर्थिक व कूटनीतिक दांव चला वह कसौटी पर खरा उतरा। आसियान देशों के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाने के उददेश्य से सरकार स्थलीय संपर्क को प्राथमिकता दे रही है। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पडाव है। भारत–म्यांमार– थाईलैंड सुपर हाईवे जो शीघ्र ही पूरी तरह खुल जाएगा। 3200 किलोमीटर लंबा यह हाईवे मोरेह (मणिपुर) से शुरू होकर म्यांमार के मांडले व यंगून होते हुए मेसोट (थाईलैंड) को जोड़ेगा। "भारत सरकार द्वारा म्यांमार में विकास संबंधी घोषित योजनाओं को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करने की दिशा में भारत सरकार आज तत्पर है। म्यांमार में भारत के राजदूत विक्रम मिस्त्री ने स्थानीय पब्लिकेशन ग्लोबल लाइट ऑफ म्यांमार को बताया कि सभी योजनाओं को शीघ्र पूर्ण करने का अभियान प्रारंभ कर दिया गया है और म्यांमार की पलेखा नदी से जोरीनपुई मिजोरम तक की 109 किलोमीटर पथ पर अक्टूबर 2017 से काम प्रारंभ हो जाएगा।"[6]

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की विदेश नीति की अग्निपरीक्षा तब देखने को मिली जब उड़ी एवं पुलवामा हमले के बाद उन्होंने पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय मंचों पर नए सिरे से घेराबंदी की। उन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान इस ओर खींचा कि पाकिस्तान आतंकवाद का निर्यातक देश बन चुका है। पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मंच पर अलग–थलग करने के लिए मोदी ने अपनी विदेश यात्राओं के दौरान अर्जित मधुर संबंधों का लाभ उठाया और इसमें पूर्णतः सफलता प्राप्त की। जो अमेरिका सदैव पाकिस्तान के साथ खड़ा रहता था, उसने साफ–साफ कह दिया कि पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद पर नकेल कसनी होगी। चीन ने भी संतुलित दृष्टिकोण अपनाया। इसका परिणाम यह हुआ कि बात–बात में परमाणु हमले की धमकी देने वाला पाकिस्तान रक्षात्मक मुद्रा में आ गया। लेकिन नरेन्द्र मोदी यहीं नहीं रुके। उन्होंने देशभर में उड़ी एवं पुलवामा हमले का जवाब देने की उठ रही जनाकांक्षाओं का ध्यान रखते हुए सेना को खली छूट दे दी कि वह अपने तरीके से इस हमले का उत्तर दें। जब सेना ने पाकिस्तान से लगी सीमा पार कर सर्जिकल एवं एयर स्ट्राइकों को अंजाम दिया तब पाकिस्तान स्तब्ध रह गया क्योंकि उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत कभी आक्रामक मुद्रा अपनाएगा। इस हमले के बाद लोगों ने मानना शुरू कर दिया कि मोदी के नेतृत्व में अब भारत के 'अच्छे दिन' और आतंकवाद के 'बुरे दिन' आ गए हैं। नरेन्द्र मोदी की विदेश नीति की सबसे बड़ी कामयाबी यह है

कि पाकिस्तान में घुसकर की गई सर्जिकल एवं एयर स्ट्राइकों पर पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है।

अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 57 इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन आफ इस्लामिक कोऑपरेशन (ओ.आई.सी.) में पाकिस्तान को अलग–थलग करने की मुहिम में जुटे हैं। इसकी शुरुआत अफ्रीकी देशों से हो चुकी है। इतना ही नहीं मोदी की विदेश नीति पाकिस्तान के भीतर भी काम कर रही है। आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं और सिंध व बलूचिस्तान में आजादी की मांग उठ रही है तो इसे प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति की सफलता ही माना जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मार्च 2020 में ईटी ग्लोबल बिजनेस समिट नई दिल्ली में बोलते हुए भारत की विदेश नीति और अर्थ नीति का सार दोस्ती को बताया। ... ''साथियों, बदलती हुई वैश्विक परिस्थितियों के बीच भारत ने भी बहुत व्यापक बदलाव किए हैं। एक कालखंड था जब भारत तटस्थ था। हम तटस्थ थे। लेकिन हमारी तटस्थता का पैरामीटर क्या था? हम तटस्थ थे किस रूप में? हमारी इस देश से भी इतनी दूरी है, उस देश से भी इतनी दूरी है, यानी मानदण्ड था कि हम किससे कितनी दूर हैं? अब बदलाव कैसे आया है? आज भी हम तटस्थ हैं। आज भी भारत का रुख तटस्थ है। लेकिन दूरी के आधार पर नहीं दोस्ती के आधार पर। अब हम किससे कितनी नजदीकी लाए हैं? तटस्थ रहते हुए भी कभी दूरी का पैरामीटर था, आज दोस्ती को हमने पैरामीटर बनाया है। हम सऊदी अरबिया के साथ भी दोस्ती करते हैं, ईरान के साथ भी दोस्ती करते हैं। हम अमेरिका से दोस्ती करते हैं हम रसिया से भी दोस्ती करते हैं। इसलिए हम तटस्थ हैं और इसलिए इन बदलावों की बारीकी को समझना, यह भी उतना आवश्यक है। एक समय था जब लोग समान दूरी बनाकर तटस्थ थे। हम समान दोस्ती करके तटस्थ हैं। उस कालखण्ड में दूरी रखकर बचने की कोशिश की गई। आज हम दोस्ती रखकर साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं। ये भारत की आज की विदेश नीति, भारत की आज की अर्थ नीति का बहुत बड़ा सार है।''[7]

''भारत किसी को भी आँख दिखाने के पक्ष में नहीं है और न ही भारत अब आँख झुका करके जीने के लिए तैयार है। दुनिया की कोई कितनी ही बड़ी ताकत क्यों न हो, भारत आँख मिलाकर के आगे बढ़ने का पक्षकार है और इसमें आँख दिखाने के हमारे सपने नहीं हैं। आँख झुकाने की हमारी तैयारी नहीं है, लेकिन विश्व के साथ आँख से आँख मिला कर के बात करने का सामर्थ्य भारत की सरकार में है।''

नरेन्द्र मोदी

नरेन्द्र मोदी सरकार की कूटनीतिक कुशलता ने विश्व को आश्वस्त किया है कि धरातल पर भारत में कारोबार करने की स्थिति अब बदल चुकी है। भारत के आंतरिक विकास के लिए बाहरी कारकों को गतिशीलता दी गई है, और इसमें कोई शक नहीं है कि मोदी सरकार ऑनलाइन के जरिए प्रक्रिया को आसान करते हुए एक ही दिन में कारोबार शुरू करवाने की कोशिश कर रही है। ठेके तथा कानून के शासन की शुद्धता को लागू करने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। आर्थिक सुधार के एजेंडे को भी सुनियोजित तरीके से लागू करवाने का प्रयास किया जा रहा है। "नतीजा यही है कि मोदी सरकार की विदेश नीति निश्चित रूप से डॉ० सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के मुकाबले ऊर्जावान रही है। तथा पड़ोस के देशों पर केन्द्रित रही है।"[8]

संदर्भ सूची

1. Shodhganga, bhanu-pratap-Mishra-cd-232-303,pdf पृ.–289
2. सार्क कंट्रीज मेकअप अराउंड 21 परसेंट ऑफ द टोटल वर्ल्ड पापुलेशन विद अराउंड 1.7 बिलियन पीपल, इंडिया मेक्स फॉर द मेजॉरिटी सार्क कंट्रीज मेकअप अराउंड 21 परसेंट ऑफ दिस रीजंस एरिया एंड पापुलेशन, श्रीधर रामास्वामी, ''इंडिया एंड इट्स इस्टर्न नेबर्सः प्रास्पेक्ट्स फॉर सब–रीजनल को–ऑपरेशन'' ओआरएफ इशू ब्रीफ,नं.–94, जून, 2015 डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू. ओआरएफऑनलाइन.ओआरजी
3. प्रद्युम्न, बी राना, इफ सार्क स्टम्बल्सः गो फॉर सब–रीजनल अल्टरनेटिव्स', आर.एस.आई.एस कामेन्ट्री नं.– 241, दिसंबर 3,2014, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.आरएसआईएस. ईडीयू.एसजी, सौरभ.एसजी, सौरभ कौशिक, ''सब–रीजनल को–ऑपरेशन इन साउथ एशियाः अ न्यू लीज आफ लाईफ, आर्टिकल नं.– 4839, फरवरी 23, 2015 कौशिक, ''सब–रीजनल को–ऑपरेशन इन साउथ एशियाः अ न्यू लीज आफ लाईफ, आर्टिकल नं.– 4839, फरवरी 23, 2015
4. मैथ्यू पी.एम. ''मैन्यूफैक्चरिंग इन इंडियाः न्यू पर्सपेक्टिव्स एंड इम्प्रेटिव्स'', योजना, अप्रैल–2015, मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टरः ग्रोथ एंड चौलेन्जेज
5. अनंत विजय एंड शिवानंद द्विवेदी, परिवर्तन की ओर, पृ.सं.–149
6. टाइम्स ऑफ इंडिया, 14 जून, 2017
7. ईटी ग्लोबल बिजनेस समिट, 6 मार्च, 2020, नई दिल्ली
8. Shodhganga, bhanu-pratap-Mishra-cd-232-303,pdf पृ.–302